विवरण

क्रम सं०	पद का नाम और वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	संयुक्त सचिव या समतुल्य (5900–8700 रु०)	1	1
2.	निदेशक या समतुल्य (4500–5700 रु०)	4	1
3.	निदेशक या समतुल्य (4100–5300 रु०)	2	—
4.	उप सचिव/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या समतुल्य (3700–5000 रु०)	29	8
5.	संयुक्त निदेशक या समतुल्य (3000–5000 रु०)	1	2
6.	अवर सचिव/उप निदेशक या समतुल्य (3000–4500 रु०)	40	12
7.	सहायक निदेशक या समतुल्य (2200–3500 रु०)	50	18
8.	अनुभाग अधिकारी या समतुल्य (ग्रुप-ख) (2000–3500 रु०)	54	14
9.	*सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (2000–3200 रु०)	2	1
10.	*सहायक प्रशासनिक अधिकारी (1640–2900 रु०)	2	—
	कुल	185	57

*ये पद अधीनस्थ कार्यालयों में है और इन्हें प्रशासनिक कारणों से राजपत्रित घोषित किया गया है।

रोजगार कार्यालयों की भूमिका

3892. **श्री सोम पाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में किसी रोजगार कार्यालय की क्या भूमिका है;

(ख) वर्ष 1992 के प्रारंभ में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कितने बेरोजगार शिक्षित लोग थे और इनमें से कितने लोगों को रोजगार कार्यालयों की मदद से रोजगार मिला;

(ग) क्या सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) रोजगार कार्यालयों की भूमिका अधिसूचित रिक्तियों के लिए उनमें पंजीकृत उम्मीदवारों को प्रायोजित करने तक सीमित है ।

(ख) दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित बेरोजगारों, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों, की संख्या (अद्यतन उपलब्ध) 211 लाख थी । रोजगार कार्यालयों द्वारा 1990 के दौरान 1.29 लाख शिक्षित नौकरी चाहने वालों को नौकरियों में लगाया गया था ।

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है । योजना में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए प्रापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार सम्भाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उचित दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है । भौगोलिक तथा फसल-वार विविधीकृत कृषीय विकास, बंजर भूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर-फार्म क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं । परिकल्पित विभिन्न उपायों से शिक्षित बेरोजगारों को भी लाभ प्राप्त होने की आशा है ।

कोयला और इस्पात उद्योग में कार्यरत मजदूरों के लिए मजदूरी

3893. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात और कोयला उद्योग में नियोजित मजदूरों के लिए मजदूरी की मौजूदा दरें क्या हैं; और

(ख) इन दरों का निर्धारण कब किया गया था और क्या हाल में इसमें कोई संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Seminar on International Labour

3894. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether any Seminar on International Labour Migration Statistics and Information Network was held by ARTEP (Asian Regional Team for Employment Promotion) of ILO at New Delhi, recently;

(b) if so, the details and outcome thereof;

(c) what is the number of Indians went abroad in 1992 and likely to be sent abroad during 1993;

(d) what steps Government are taking for having common approach for deployment of workers abroad and also for checking illegal migration of workers; and

(e) whether statistical data are available in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (e) A Regional Seminar on International Labour Migration Statistics and Information Networking in Asia organised by the ARTEP, New Delhi, under the auspices of the UNDP/ILO Asian Regional Programme on International Labour Migration, with the broad aims of identifying gaps and weaknesses in the existing systems of information, evolving concrete recommendations for quick processing of information generation at the National level, and examining the possibilities of information networking within the region was held on 17-19 March, 1993, in New Delhi. Representatives from thirteen countries of Asia, viz, Bangladesh, People's Republic of China, India, Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Myanmar, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam attended the Seminar. The participants included officials of the Ministries of Labour and Central Banks of the various governments, workers and employers organisations, NGOs, research institutions, resource per-